

विजय पाल

बनाम

दिल्ली राज्य (जी. एन. सी. टी.)

(आपराधिक अपील संख्या 2153/2011)

10 मार्च, 2015

[न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एन. वी. रमना]

दंड संहिता, 1860-धारा 302-के तहत अभियोजन-पति के कारण अपनी पत्नी की मौत-शादी के 11 साल बाद-पत्नी को आग लगाकर-मृत्यु पूर्व बयान-निम्नलिखित न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया: दोषसिद्धि उचित थी-मृत्यु पूर्व बयान, पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट, मृतक के भाई व पिता और पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सक की मौखिक गवाही, घटना स्थल से जब्त सामान, यह सिद्ध करते हैं कि घटना आकस्मिक नहीं थी- मृतक की नाबालिग बेटी का साक्ष्य जिसे पक्षद्रोही घोषित किया गया था, चिकित्सीय साक्ष्यों की दृष्टि से अविश्वसनीय है- अन्यत्र रहने की दलील भी अधूरी है और तर्कसंगत नहीं है-दोषसिद्धि बरकरार रखी जाती है।

मृत्यु पूर्व बयान-साक्ष्यात्मक मूल्य-पर चर्चा की गई।

साक्ष्य-चिकित्सीय गवाही बनाम चश्मदीद गवाही- साक्ष्यात्मक मूल्य-पर चर्चा की गई।

साक्ष्य-अन्यत्र उपस्थिति-अभिनिर्धारित: अन्यत्र उपस्थिति की दलील को साबित करने का भार अभियुक्त पर है-अभियुक्त द्वारा दलील को सकारात्मक साक्ष्य द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए-याचिका तभी सफल हो सकती है जब यह दिखाया जाए

कि आरोपी प्रासंगिक समय पर इतना दूर था कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं हो सके।

न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया :-

1. मौखिक साक्ष्य और घटना स्थल से जब्त की गई वस्तुओं से, यह स्पष्ट है कि मृतक को जलने की चोटें लगी थीं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह मृतक की नाबालिग बेटी पीडब्लू-3 थी, जिसने झगड़ा देखा और अपने नाना-नानी के घर पहुंच गई। [पैरा 11] [404-सी-डी]

2. विचारण न्यायाधीश ने यह पता लगाने के लिए पीडब्लू-3 से प्रासंगिक सवाल पूछा है कि क्या वह सवालों को समझने और अदालत में गवाही देने की स्थिति में थी। पक्षद्रोही घोषित किए जाने पर, उसका प्रतिपरिक्षण किया गया। उसने पहले गवाही दी कि उसे नहीं पता था कि उसकी मां को किसने अस्पताल पहुंचाया था और उसके बाद उसने यह कहते हुए अपना रुख बदल लिया कि उसके चाचा ने उसकी मां को पहुंचाया था। जैसा कि उसकी गवाही से पता चलता है कि उसने घटना के समय अपने पिता के ठिकाने का उल्लेख नहीं किया है। मां को अस्पताल में कैसे स्थानांतरित किया गया, इसके बारे में उनकी अनभिज्ञता से पता चलता है कि उसने अपने पिता को बचाने के लिए उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। [पैरा 11] [404-डी-एच]

3. विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा जताया है। पीडब्लू5, जिसने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने अपनी प्रतिपरीक्षा में इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इनकार किया कि मृतक को लगी चोटें चूल्हे के पिन लगाने पर चूल्हे से मिट्टी का तेल उसके शरीर पर गिरने के कारण लगी होंगी और मिट्टी के तेल का डिब्बा फर्श पर गिरने के कारण भी। उसने बिना किसी लाग-लपेट के कहा है कि मृतक को लगी चोटें दुर्घटनावश जलने के कारण संभव नहीं थीं।

एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, मृतक के सिर के बालों पर मिट्टी के तेल की उपस्थिति और मृतक के स्वरयंत्र में धूल के कणों की उपस्थिति से स्पष्ट है कि मृतक की खोपड़ी पर मिट्टी का तेल डाला गया था, जो दुर्घटनावश नहीं हुआ होगा। मृतका की बेटी, पीडब्लू-3, दस साल की युवा लड़की की गवाही कि उसकी मां के शरीर पर गलती से मिट्टी का तेल गिर गया था, इस प्रकार चिकित्सीय गवाही को चश्मदीद गवाही के मुकाबले तौलने पर बिल्कुल अविश्वसनीय है। [पैरा 12 और 13] [405-एफ-जी; 406-सी-डी, ई-जी]

4. यह सत्य है कि चिकित्सीय साक्ष्य का मूल्य केवल पुष्टिकारक होता है। यह भी सच है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सक के सबूत को किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं माना जा सकता। चिकित्सक के साक्ष्य का महत्व मृत व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों और हथियार के संभावित उपयोग पर निर्भर करता है और फिर यह अभियोजक का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों से पुष्टिकारक साक्ष्य को अभिलेख पर उपलब्ध कराए। यह भी एक स्वीकृत सिद्धांत है कि पाठ्यपुस्तकों में दिए गए बयानों की तुलना में पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन महत्व देने का मतलब यह नहीं है कि किसी चिकित्सीय गवाही के प्रत्येक बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही वह स्व-विरोधाभासी हो। यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी चिकित्सीय गवाह द्वारा दी गई राय इस विषय पर अंतिम शब्द होना आवश्यक नहीं है। ऐसी राय का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि राय तर्क या निष्पक्षता से रहित है, तो अदालत उस राय पर चलने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा, चश्मदीद गवाहों के बयान जिनका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना है को बाहर करने के लिए चिकित्सीय गवाहों के काल्पनिक उत्तरों को अनुचित प्रधानता देना

गलत होगा और चिकित्सीय साक्ष्य को 'स्थिर' मानते हुए उन्हें परिवर्तनीय नहीं माना जा सकता है। जहां चश्मदीद गवाहों के बयान प्रामाणिक और विश्वास करने योग्य पाए जाते हैं, वहां वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सीय राय को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। [पैरा 13] [406-जी; 407-बी बी-जी]

सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य 1983 (2) एससीसी 174, हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह 2002 (1) एससीआर 208=2002 (2) एसईसी 426, मो. जाहिद बनाम तमिलनाडु राज्य 1999 (6) एससीसी 120, हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ 1999 (3) एससीआर 529=1999 (5) एसईसी 96 और अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2010 (13) एससीआर 311=2010 (10) एसईसी 259—संदर्भित।

5. यह कहना सही नहीं है कि जब मृतिका 100% जल गई थी, तो वह अपने भाई को कोई बयान नहीं दे सकती थी। यदि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान बिल्कुल विश्वसनीय है और ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि मृतक ऐसी स्थिति में था या थी कि वह किसी गवाह को मृत्यु पूर्व बयान नहीं दे सकता था या सकती थी, इसे खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है। मौजूदा मामले में, पीडब्लू-1 तुरंत मृतका के घर पहुंचा और उसने उसे बताया कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था। अपीलकर्ता द्वारा दी गई यह दलील कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसका पैसा ससुराल वालों के पास जमा था और वे वापस करने के इच्छुक नहीं थे, वास्तव में सच नहीं है, क्योंकि इस आशय का कोई सुझाव भी नहीं है। [पैरा 20 और 21] [411-डी-जी]

मफाभाई नागरभाई रावल बनाम गुजरात राज्य 1992 (4) एससीसी 69; मध्य प्रदेश राज्य बनाम दल सिंह और अन्य 2013 (8) एससीआर 968 = 2013 (14) एसईसी 159—पर भरोसा किया गया।

लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य 2002 (6) एससीसी 710; बाबूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2003 (5), पूरक एससीआर 54=2003 (12) एससीसी 490; प्रकाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1992 (4) एससीसी 225—संदर्भित।

6. जब किसी अभियुक्त द्वारा अन्यत्र रहने की दलील दी जाती है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा मौके पर उपस्थिति के संबंध में जिम्मेदारी स्थापित करने के बाद, सकारात्मक साक्ष्य द्वारा इसे स्थापित करने का दायित्व उस पर होता है। आरोपी द्वारा अन्यत्र रहने की दलील को साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए गए हैं, वे अस्पष्ट हैं और वास्तव में तर्कसंगत नहीं हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त ने पूरी निश्चितता के साथ साबित कर दिया है ताकि घटना स्थल पर उसकी मौजूदगी की संभावना को खत्म किया जा सके। आरोपी पर बोझ काफी भारी है और उसे अन्यत्र रहने की दलील को प्रमाणिकता के साथ स्थापित करना होता है। वर्तमान मामले में, ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि किसी अन्य स्थान पर उपस्थिति के कारण अभियुक्त की अपराध स्थल पर उपस्थिति भौतिक असंभवता थी। याचिका तभी सफल हो सकती है जब यह दिखाया जाए कि आरोपी प्रासंगिक समय पर इतना दूर था कि वह उस स्थान पर मौजूद नहीं हो सकता था जहां अपराध किया गया था। डीडब्ल्यू-1 का साक्ष्य जो न केवल अधूरा है बल्कि तर्क को भी खारिज करता है किसी आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है। जब विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अन्यत्र होने की दलील पर अविश्वास किया है, जो तथ्य की समवर्ती

खोज है, तो इसे खारिज करने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 23 और 25) (412-ई; 414-ई-एफ; 415-ए-बी)

बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य 1996 (8) पूरक एससीआर 225=1997(1) एससीसी 283; उरप्रीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2002 (2) पूरक एससीआर 337=2002 (8) एससीसी 18, एस.के. सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य 2010 (10) एससीआर 503=2010 (8) एससीसी 430 और जितेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य 2012 (4) एससीआर 408=2012 (6) एससीसी 204; दूध नाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1981 (1) एससीसी 166—पर भरोसा किया गया।

निर्णय विधि संदर्भ

1983 (2) एससीसी 174	संदर्भित किया गया	पैरा 13
2002 (1) एससीआर 208	संदर्भित किया गया	पैरा 13
2002 (2) एससीसी 426	संदर्भित किया गया	पैरा 13
1999 (6) एससीसी 120	संदर्भित किया गया	पैरा 13
1999 (3) एससीआर 529	संदर्भित किया गया	पैरा 13
2010 (13) एससीआर 311	संदर्भित किया गया	पैरा 13
2002 (6) एससीसी 710	संदर्भित किया गया	पैरा 16
2003 (5) पूरक एससीआर 54	संदर्भित किया गया	पैरा 18
1992 (4) एससीसी 225	संदर्भित किया गया	पैरा 19
1992 (4) एससीसी 69	भरोसा किया गया	पैरा 21
2013 (8) एससीआर 968	भरोसा किया गया	पैरा 22

1996 (8) पूरक एससीआर 225	भरोसा किया गया	पैरा 23
2002 (2) पूरक एससीआर 337	भरोसा किया गया	पैरा 23
2010 (10) एससीआर 503	भरोसा किया गया	पैरा 23
2012 (4) एससीआर 408	भरोसा किया गया	पैरा 23
1981 (1) एससीसी 166	भरोसा किया गया	पैरा 25

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 2153/2011

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली की आपराधिक अपील संख्या 417/2001 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 31.08.2009 से।

नूपुर चौधरी (ए. सी.), जी. माधवी अपीलार्थी की ओर से।

डब्ल्यू. ए. कादरी, राधाकांत त्रिपाठी, अनिल कटियार उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय, **न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, जे.** द्वारा पारित किया गया -

1. इस अपील में, 2001 की आपराधिक अपील संख्या 417 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित 31.8.2009 के फैसले और आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत खंड पीठ ने 1998 के सत्र न्यायालय के मामला संख्या 27 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दिल्ली के दिनांक 17.01.2001 के फैसले और आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को खारिज कर दिया है, जिसके तहत ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में "आईपीसी") की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

2. अनावश्यक विवरणों को हटाते हुए अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतिका सावित्री ने अपीलकर्ता के साथ घटना की तारीख यानि 2.11.1997 से लगभग ग्यारह साल पहले विवाह किया था। मृतिका का मायका आधा किलोमीटर की दूरी पर

स्थित है। मनहूस दिन यानी 2.11.1997 को लगभग 11:00 बजे, मृतक की बेटी सीमा, पीडब्लू-3, उम्र लगभग दस वर्ष, अपने दादा शिवचरण, पीडब्लू-8 के घर दौड़ती हुई आई और उन्हें तथा मृतिका के भाई सतीश, पीडब्लू 1, को सूचित किया कि उसके पिता उसकी माँ को जलाने की धमकी दे रहे थे। सूचना ने पीडब्लू 1 और 8 को मृतक के घर तीव्रता से जाने के लिए मजबूर किया और, जैसा कि तथ्यात्मक साँचे से पता चलता है, पीडब्लू-1, उम्र में छोटा होने के कारण, अपने पिता से पहले अपनी बहन के घर पहुंचा और पाया कि उसकी बहन जल रही थी और उसने उसे बताया कि आरोपी-अपीलकर्ता ने ही उस पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी। भाई ने आग बुझाने के लिए मृतिका पर पानी डाला और उसके बाद उसे दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले गए जहां सुविधा के अभाव में उसे भर्ती नहीं किया जा सका और उसके बाद वे उसे सफदरजंग अस्पताल ले आए जहां उसे भर्ती कर लिया गया। उपचार का लाभ उठाने के बावजूद, उसने 3.11.1997 को दोपहर के करीब अंतिम सांस ली। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि मृतक को उसके पिता और भाई द्वारा अस्पताल ले जाने के बाद, दो पड़ोसी, शंकर लाल और सुरेंद्र, क्रमशः पीडब्लू-2 और पीडब्लू-4, मंगोल पुरी के पुलिस स्टेशन गए और घटना की सूचना डीडी-73 दिनांक 2.11.1997 द्वारा दी गई जिसके आधार पर एसआई विजेंदर सिंह, पीडब्लू-21, घटना स्थल पर गए जहां वह मृतिका की बेटी पीडब्लू-3 से मिले, और उन्हें पता चला कि उसके माता-पिता के बीच झगड़ा हुआ था और उसकी माँ जल गई थी और उसे अस्पताल ले जाया गया था।

3. इसी बीच, सफदरजंग अस्पताल से पुलिस स्टेशन को सूचना मिली कि मृतक को वहां भर्ती कराया गया है और उक्त सूचना के आधार पर पुलिस अस्पताल पहुंची जहां उनकी मुलाकात पीडब्लू 1 और 8 से हुई। जैसे कि मौत होने के बाद अभियोजन का मामला और खुला, उन्होंने जांच आगे बढ़ाई, जले हुए कपड़े, एक रजाई, एक

प्लास्टिक की छड़ी, एक माचिस की डिब्बी और माचिस की तीली जब्त की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच एजेंसी ने जांच के दौरान 03.11.1997 को पति को गिरफ्तार कर लिया और कई गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया, जिसने मामले को सत्र न्यायालय में भेज दिया और अंततः इसका मुकदमा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा चलाया गया।

4. आरोपी ने अपना अपराध अस्वीकार कर दिया और निवेदन किया कि वह घर पर नहीं था क्योंकि वह अपनी बहन श्यामवती, डीडब्ल्यू-1, एमजे-1/61, विकास पुरी, दिल्ली के घर गया था और मुकदमा चलाए जाने के लिए दावा किया।

5. अभियोजन पक्ष ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए 21 गवाहों का परीक्षण किया और कई दस्तावेजों का प्रदर्शन किया। प्रत्यक्षदर्शी और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप को पूरी तरह से स्थापित किया था और तदनुसार उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई, जैसा कि यहां पहले बताया गया है।

6. अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने सबूतों की पुनः समीक्षा की और मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा और भाई की गवाही पर भरोसा किया और आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए पाया कि विद्वान विचारण न्यायाधीश ने दोषसिद्धि दर्ज करने में वास्तव में कोई गलती नहीं की थी। इस दृष्टिकोण के चलते उसने अपील खारिज कर दी।

7. हमने अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता (न्याय मित्र) सुश्री नूपुर चौधरी और राज्य के वकील श्री डब्ल्यू. ए. कादरी को सुना है।

8. विद्वान न्याय मित्र सुश्री नूपुर चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ गलती से दोषसिद्धि दर्ज की है, हालांकि मृतक की बेटी पीडब्लू-3 ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया था और उसके मुख्य गवाह होने के नाते, आरोपी बरी होने का हकदार है। उनकी ओर से यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय ने मृतिका के मृत्यु पूर्व मौखिक बयान पर भरोसा करके गलती की है, जबकि वह गंभीर रूप से जल गई थी और ऐसी स्थिति में उसके लिए अपने भाई को कुछ भी बताना संभव नहीं हो सका। उन्होंने उच्च न्यायालय के उस फैसले की गंभीरता से आलोचना की है, जिसमें आरोपी द्वारा दी गई अन्यत्र होने की याचिका को स्वीकार नहीं किया गया था, जिसका ठोस आधार था, क्योंकि उस दिन "भैया दूज" था और इसलिए आरोपी परंपरा अनुसार अपनी बहन के घर गया था।

9. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान वकील श्री कादरी का तर्क है कि यद्यपि मृतिका की बेटी, पीडब्लू-3, पक्षद्रोही हो गई है, फिर भी उसके साक्ष्य को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभियोजन और बचाव दोनों गवाही के ऐसे हिस्से जो उनके अनुकूल हों पर भरोसा कर सकते हैं। उनका आगे यह भी कहना है कि मृतक के भाई द्वारा अपनी गवाही में दिया गया मौखिक मृत्युपूर्व बयान किसी भी संदेह से परे साबित हुआ है और लगातार जिरह के बावजूद, वह पूरी तरह से दृढ़ रहा है और उसके संस्करण को खारिज करने के लिए कुछ भी नहीं मिला है और इसलिए, न तो विद्वान विचारण न्यायाधीश और न ही उच्च न्यायालय ने इस पर भरोसा करने में गलती की है। अन्यत्र होने की दलील के संबंध में, विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत किया कि उक्त दलील को आरोपी द्वारा कानून के तहत स्थापित नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर लाए गए तथ्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि प्रासंगिक समय पर वह घर पर था। संक्षेप में, उनके द्वारा यह आग्रह किया गया है

कि जब इन पहलुओं की उचित तरीके से सराहना की जाती है, तो संचयी प्रभाव यह दिखाने में काफी हद तक मदद करेगा कि अपीलकर्ता को विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और उच्च न्यायालय ने उससे बिल्कुल सही सहमति जताई है।

10. बार में उठाए गए प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को समझने के लिए, हमने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को संबंधित उत्सुकता के साथ पढ़ा है और अभिलेख पर मौजूद सबूतों की सावधानीपूर्वक जांच की है। जैसा कि हमने पाया, मूल रूप से सात गवाह हैं जिनके साक्ष्य महत्वपूर्ण हैं, वे हैं मृतक के भाई सतीश, पीडब्लू-1, मृतक के पिता शिवचरण, पीडब्लू-8, डॉ. जीके चौबे, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, पीडब्लू -5, सीमा, मृतक की बेटी, पीडब्लू-3, शंकर लाल, पीडब्लू-2 और सुरेंद्र, पीडब्लू-4 जिन्होंने पहली बार पुलिस को सूचित किया और विजेंद्र सिंह, पीडब्लू-21, उप-निरीक्षक जिन्होंने बयान दर्ज किया। इस समय, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि पीडब्लू-3 के अलावा, पीडब्लू 2, 4 और 8 को भी अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था और राज्य द्वारा उनका प्रतिपरिक्षण किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या अभिलेख पर लाए गए तथ्य प्रदर्श पीडब्लू-1/ए, पीडब्लू-1/बी, पीडब्लू-1/डी, पीडब्लू-1/ई, पीडब्लू-1/एफ और प्रदर्श पी-2 जो जब्त किए गए थे की जांच पर दोष सिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

11. मौखिक साक्ष्य और घटना स्थल से जब्त की गई वस्तुओं से, यह स्पष्ट है कि मृतिका को जलने की चोटें लगी थीं, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह मृतक की बेटी पीडब्लू-3 थी, जिसने झगड़ा देखा और अपने नाना-नानी के घर पहुंच गई। विद्वान विचारण न्यायाधीश ने यह पता लगाने के लिए उससे संबंधित प्रश्न पूछा है कि क्या वह प्रश्नों को समझने और अदालत में गवाही देने की स्थिति में है। अपने साक्ष्य में, उसने कहा था कि उस दिन लगभग 11.00 बजे उसकी मां बच्चों के लिए खाना बना

रही थी और चूल्हा खाली होने के कारण वह उसमें मिट्टी का तेल डाल रही थी और उसके बाद जब उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की, चूल्हे के नोजल से केरोसिन तेल नहीं निकल रहा था, तभी मृतिका ने नोजल में पिन डाला और तेल उसके ऊपर छिड़क गया और इसी क्रम में वह आग की चपेट में आ गयी। यहां यह नोट करना प्रासंगिक है कि उसने पहले गवाही दी थी कि उसे नहीं पता था कि उसकी मां को किसने अस्पताल पहुंचाया था और उसके बाद उसने यह कहते हुए अपना रुख बदल दिया कि उसके चाचा ने उसकी मां को अस्पताल पहुंचा दिया था। जैसा कि उसकी गवाही से पता चलता है कि उसने घटना के समय अपने पिता के ठिकाने का उल्लेख नहीं किया है। मां को अस्पताल में कैसे स्थानांतरित किया गया, इस बारे में उनकी अनभिज्ञता से पता चलता है कि जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही विश्लेषण किया है, उसने अपने पिता को बचाने के लिए उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इस बात को स्थगित रखते हुए कि आरोपी द्वारा ली गई अन्यत्र होने की दलील साबित हुई है या नहीं, इस पर बाद के चरण में विचार किया जाएगा, हम अन्य गवाहों के सबूतों को बारीकी से जाँचना उचित समझते हैं। आरोपी के भाई पीडब्लू-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सीमा, पीडब्लू-3 से जानकारी मिलने के बाद, उसके पिता और वह तेजी से मृतिका के घर पहुंचे। जैसा कि गवाही से स्पष्ट है, वह सबसे पहले बहन के घर पहुंचा और पाया कि वह जल रही थी और उसने उसे बताया कि उसके जीजा ने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। उसने यह भी कहा है कि बच्चों को आरोपी को नहीं दिया जाना चाहिए। उसने अस्पताल जाने और मौके पर नक्शा कैसे तैयार किया गया और गवाहों की मौजूदगी में सामान कैसे जब्त किया गया, इस बारे में विस्तार से बताया। प्रतिपरिक्षण में, घर में पति की अनुपस्थिति, उसके द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की साजिश या ऐसी किसी भी बात के बारे में कोई सुझाव नहीं दिया गया है जिससे उसकी गवाही पर असर पड़ेगा। प्रतिपरिक्षण में यह लाने की मांग की गई है कि मृतक के

कमरे में कोई मौजूद नहीं था और कुछ अन्य सवाल भी हैं जिनका घटना से कोई लेना-देना नहीं है। उसे यह सुझाव दिया गया है कि उसकी बहन और आरोपियों ने घर खरीदने के लिए उसके पिता, पीडब्लू-8 के पास 90,000/- रुपये रखे थे और जब उन्होंने पैसे वापस करने से इनकार कर दिया, तो मौका पाकर उन्होंने आरोपी को झूठा फंसा दिया।

12. इस स्तर पर यह कहना उचित होगा कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा जताया है। डॉ. जीके चौबे, पीडब्लू5, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया था, ने निम्नलिखित चोटें पाईं:-

"सिर की त्वचा सहित शरीर के पूरे सतह क्षेत्र पर सतही से गहरी जलन की चोट, कई स्थानों पर त्वचा छिल गई, उतकों के नीचे का किनारा चमकदार लाल हो गया और विभिन्न क्षेत्रों में त्वचा काली पड़ गई। तलवों पर त्वचा छिल गई थी, लेकिन हथेलियों पर नहीं। मध्यवर्ती मैलियोस के ऊपर बाएं पैर में वेनिसेक्शन मौजूद था।"

यह मृत्युपूर्व 100 प्रतिशत गहरा जलने के घाव थे। आंतरिक जांच से पता चला कि स्वरयंत्र में कालिख के कण थे और बाकी अंगों में जमाव पाया गया।"

13. जिरह में उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि मृतक को लगी चोटें चूल्हे को पिन लगाने पर मिट्टी का तेल उसके शरीर पर गिरने से और मिट्टी के तेल का डिब्बा फर्श पर गिरने से लगी होंगी। उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कहा है कि मृतक को लगी चोटें दुर्घटनावश जलने के कारण संभव नहीं थीं। हाईकोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्लू 20/बी, पर संज्ञान लिया है जिससे यह स्पष्ट है कि गैस तरल क्रोमैटोग्राफी द्वारा विश्लेषण से पता चला है कि मृतक के सिर के बालों पर

मिट्टी के तेल के अवशेष पाए गए थे। गौरतलब है कि मृतक के सिर के बालों पर मिट्टी के तेल की मौजूदगी और मृतक के स्वरयंत्र में धूल के कणों की मौजूदगी से स्पष्ट है कि मृतक की खोपड़ी पर मिट्टी का तेल डाला गया था, जो दुर्घटनावश नहीं हुआ होगा। बेटी, सीमा, पीडब्लू-3, दस साल की एक युवा लड़की की गवाही कि मिट्टी का तेल गलती से उसकी माँ के शरीर पर गिर गया, इस प्रकार बिल्कुल अविश्वसनीय है। जब हम चिकित्सीय साक्ष्यों को चश्मदीद साक्ष्यों की तुलना में तौलते हैं तो हम ऐसा सोचने के लिए प्रवृत्त होते हैं। इसमें कोई विवाद नहीं है कि चिकित्सा साक्ष्य का मूल्य केवल पुष्टिकारक है। यह साबित करता है कि चोटें उसी तरीके से पहुंचाई गई होंगी जैसा कि आरोप लगाया गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। बचाव पक्ष चिकित्सीय साक्ष्य का उपयोग यह साबित करने के लिए कर सकता है कि चोटें संभवतः कथित तरीके से नहीं हुई होंगी और इस तरह चश्मदीद गवाहों को अविश्वसनीय माना जा सकता है। जब तक चिकित्सीय साक्ष्य इतने आगे नहीं बढ़ जाते कि चश्मदीदों द्वारा बताए गए तरीके से चोट लगने की सभी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए, तब तक चश्मदीद गवाहों की गवाही और चिकित्सीय साक्ष्य को उनके बीच कथित असंगतता के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। यह भी सच है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने आप में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य को किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं माना जा सकता। चिकित्सक के साक्ष्य का महत्व मृत व्यक्ति के शरीर पर दिखाई देने वाली चोटों और हथियार के संभावित उपयोग पर निर्भर करता है और फिर यह अभियोजक का कर्तव्य और दायित्व होगा कि वह अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों से पुष्टिकारक साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराए। यह भी एक स्वीकृत सिद्धांत है कि पाठ्यपुस्तकों में दिए गए विवरणों की तुलना में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक के साक्ष्य को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए, लेकिन महत्व देने का मतलब यह नहीं है कि चिकित्सीय गवाह

द्वारा दिए गए प्रत्येक बयान को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही वह स्व-विरोधाभासी हो। यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी चिकित्सीय गवाह द्वारा दी गई राय इस विषय पर अंतिम शब्द नहीं होनी चाहिए। ऐसी राय का परीक्षण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। यदि राय तर्क या निष्पक्षता से रहित है, तो अदालत उस राय पर चलने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा, चश्मदीद गवाहों के बयान जिनका स्वतंत्र रूप से परीक्षण किया जाना है को बाहर करने के लिए चिकित्सीय गवाहों के काल्पनिक उत्तरों को अनुचित प्रधानता देना गलत होगा और चिकित्सीय साक्ष्य को 'स्थिर' मानते हुए उन्हें परिवर्तनीय नहीं माना जा सकता है। जहां चश्मदीद गवाहों के बयान प्रामाणिक और विश्वास करने योग्य पाए जाते हैं, वहां वैकल्पिक संभावनाओं की ओर इशारा करने वाली चिकित्सीय राय को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। [देखें: सोलंकी चिमनभाई उकाभाई बनाम गुजरात राज्य (1983) 2 एसईसी 114 हरियाणा राज्य बनाम राम सिंह (2002) 2 एससीसी 426, मो. जाहिद बनाम तमिलनाडु राज्य (1999) 6 एससीसी 120, हरियाणा राज्य बनाम भागीरथ (1999) 5 एससीसी 96 और अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2010) 10 एससीसी 259]

14. अभिलेख पर लाए गए चिकित्सीय साक्ष्य और इस तरह के साक्ष्य को कैसे महत्व दिया जाना चाहिए, इसके बारे में बताने के बाद, हमें लगता है कि मौखिक मृत्युपूर्व बयान पर ध्यान देना उचित है, जिस पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी भरोसा जताया है। भाई, सतीश, पीडब्लू-1 की गवाही के अनुसार, घटनास्थल पर पहुंचने के बाद उसने अपनी बहन को जलती हुई पाया और उसने कहा था कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डाला है और उसे आग लगा दी है। यह दिखाने के लिए तथ्य है कि पिता, शिवचरण, पीडब्लू-8, अपने बेटे के बाद पहुंचे। अभियोजन पक्ष ने पिता के देर से आने के कारण बताया है।

15. अपीलकर्ता के विद्वान वकील की दलील यह है कि मौखिक मृत्युपूर्व बयान में आंतरिक सच्चाई का अभाव है और यह स्वीकृति के योग्य नहीं है। इस समय हम कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करना उचित समझते हैं कि मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा की जांच कैसे की जानी है।

16. **लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य** (2002) 6 एससीसी 110, के मामले में, संविधान पीठ ने इस प्रकार कहा है:

"मृत्युपूर्व घोषणा की स्वीकार्यता के बारे में न्यायिक सिद्धांत यह है कि ऐसी घोषणा चरम सीमा पर की जाती है, जब पक्ष मृत्यु के कगार पर होता है और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ का हर मकसद खामोश हो जाता है, और मनुष्य को केवल सत्य बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली विचार से प्रेरित किया जाता है। इसके बावजूद, कई परिस्थितियों के अस्तित्व के कारण इस प्रकार के साक्ष्य को दिए जाने वाले महत्व पर विचार करते समय बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए जो उनकी सच्चाई को प्रभावित कर सकती है। जिस स्थिति में एक व्यक्ति मृत्यु शय्या पर है वह इतनी गंभीर और शांत है कि कानून में उसके कथन की सत्यता को स्वीकार करने का कारण है। यही कारण है कि शपथ और प्रतिपरिक्षण की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि अभियुक्त के पास जिरह करने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए अदालतें इस बात पर जोर देती हैं कि मृत्युपूर्व बयान इस तरह का होना चाहिए कि न्यायालय को उसकी सत्यता और शुद्धता पर पूरा भरोसा हो। हालाँकि, अदालत को यह देखने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है कि मृतक का बयान या तो सिखाने या उकसाने या कल्पना का

परिणाम नहीं था। न्यायालय को यह भी तय करना होगा कि मृतक की मानसिक स्थिति ठीक थी और उसे हमलावर को देखने और पहचानने का अवसर मिला था। इसलिए, सामान्य तौर पर, न्यायालय यह संतुष्ट करने के लिए कि क्या मृतक मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए मानसिक रूप से उपयुक्त स्थिति में था, चिकित्सीय राय पर निर्भर करती है। लेकिन जहां प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मृतक घोषणा करने के लिए स्वस्थ और सचेत स्थिति में था, तो चिकित्सा राय मान्य नहीं होगी, न ही यह कहा जा सकता है कि घोषणाकर्ता, मृत्यु पूर्व दिया गया बयान स्वीकार्य नहीं है चूंकि मृतक के दिमाग की स्वस्थता के बारे में चिकित्सक का कोई प्रमाणन नहीं है। मृत्यु पूर्व बयान मौखिक या लिखित हो सकता है और संचार का कोई भी पर्याप्त तरीका चाहे वह शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या अन्यथा पर्याप्त होगा, बशर्ते संकेत सकारात्मक और निश्चित हो।”

17. उपरोक्त निर्णय यह बिल्कुल स्पष्ट करता है कि मृत्यु पूर्व बयान मौखिक या लिखित हो सकता है और संचार का कोई भी पर्याप्त तरीका चाहे शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या अन्यथा पर्याप्त होगा, बशर्ते संचार सकारात्मक और निश्चित हो। इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर यंत्रवत् भरोसा नहीं किया जा सकता। वास्तव में, यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह मृत्यु पूर्व दिए गए बयान की जांच अध्ययन के साथ करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह स्वैच्छिक है, सच्चा है और मन की सचेत अवस्था में दिया गया है और इसके अलावा यह बिना किसी प्रभाव के है।

18. इस समय, हम **बाबूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (2003) 12 एससीसी 490 से एक अंश उद्धृत कर सकते हैं जिसमें साक्ष्य में मृत्यु पूर्व बयान का महत्व बताया गया है:-

"7. ... एक व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु का सामना कर रहा है, जिसके इस दुनिया में बने रहने की छाया भी व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है, झूठ का हर उद्देश्य नष्ट हो जाता है। केवल सच बोलने के लिए सबसे शक्तिशाली नैतिक कारणों से मन बदल जाता है। एक मरते हुए व्यक्ति के शब्दों में बहुत गंभीरता और पवित्रता जुड़ी होती है क्योंकि मरने के कगार पर एक व्यक्ति झूठ बोलने या किसी निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई मामला गढ़ने की संभावना नहीं रखता है। कहावत है "कोई व्यक्ति अपने निर्माता से मुंह में झूठ लेकर नहीं मिलेगा" (नेमो मोरिटुरस प्रीसुमितूर मेंटिरी)। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा, "सच्चाई एक मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठती है"। सामान्य सिद्धांत जिस पर साक्ष्य की प्रजाति को स्वीकार किया जाता है वह यह है कि वे चरम सीमा पर की गई घोषणाएं हैं, जब पक्ष मृत्यु के बिंदु पर होता है, और जब इस दुनिया की हर उम्मीद खत्म हो जाती है, जब झूठ बोलने का हर मकसद शांत हो जाता है और मन प्रेरित होता है सच बोलने के सबसे सशक्त विचार से; स्थिति इतनी गंभीर है कि कानून इसे अदालत में दिलाई गई सकारात्मक शपथ के बराबर दायित्व बनाने पर विचार करता है।"

19. मृत्यु पूर्व मौखिक घोषणा से निपटते हुए, **प्रकाश बनाम मध्य प्रदेश राज्य** (1992) 4 एससीसी 225 में दो न्यायाधीशों की खंडपीठाने इस प्रकार कहा है:

"11. ... सामान्य तौर पर, पिता सहित परिवार के सदस्यों से अपेक्षा की जाती थी कि वे पीड़ित से पहले अवसर पर हमलावरों के नाम पूछें और यदि पीड़ित बात करने की स्थिति में है, तो यह उचित रूप से अपेक्षित है कि यदि उसने हमलावरों को पहचान लिया है तो वह हमलावरों के नाम बता देगा। मौजूदा मामले में यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मृतक हमलावरों को पहचानने की स्थिति में नहीं था क्योंकि यह किसी का मामला नहीं है कि मृतक आरोपी व्यक्तियों को नहीं जानता था। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि पूछे जाने पर मृतक हमलावरों का नाम बताएगा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने मृत्यु पूर्व दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया है और हमें नहीं लगता कि इस तरह का निष्कर्ष विकृत है और इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।"

20. इस प्रकार, कानून बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि मरने से पहले दिया गया बयान पूरी तरह से विश्वसनीय है और ऐसा कुछ भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है कि मृतक ऐसी स्थिति में था, वह किसी गवाह को मृत्यु पूर्व बयान नहीं दे सकता था, इसे खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है। मौजूदा मामले में, पीडब्लू-1 तुरंत मृतक के घर पहुंचा और उसने उसे बताया कि उसके पति ने उस पर मिट्टी का तेल डाला था। अपीलकर्ता द्वारा दी गई यह दलील कि उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसका पैसा ससुराल वालों के पास जमा था और वे वापस करने के इच्छुक नहीं थे, वास्तव में सच नहीं है, क्योंकि इस आशय का कोई सुझाव भी नहीं है।

21. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब मृतिका 100% जल गई थी, तो वह अपने भाई को कोई बयान नहीं दे सकती थी। इस संबंध में, हम **मफाभाई नागरभाई रावल बनाम गुजरात राज्य (1992) 4 एससीसी 69** के फैसले का

हवाला दे सकते हैं, जिसमें यह माना गया है कि 99% जले हुए व्यक्ति को मृत्यु पूर्व बयान देने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम माना जा सकता है। उक्त मामले में न्यायालय की राय थी कि जब तक कोई अंतर्निहित और स्पष्ट दोष मौजूद न हो, विचारण न्यायालय को चिकित्सक की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए थी। मामले के तथ्यों के आलोक में मृत्यु पूर्व दिया गया बयान विश्वसनीय पाया गया।

22. **मध्य प्रदेश राज्य बनाम दल सिंह और अन्य (2013) 14 एससीसी 159** में, दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मृतक के मृत्यु पूर्व दिए गए बयान पर भरोसा जताया, जो 100% जल गया था, इस आधार पर कि मृत्यु के समय दिया गया बयान विश्वसनीय पाया गया था।

23. इस समय, हमें लगता है कि अपीलकर्ता द्वारा पेश की गई अन्यत्रता की दलील से निपटना उचित है। जैसा कि प्रदर्शित है, विचारण न्यायालय ने अन्यत्र होने की दलील को खारिज कर दिया है। जब किसी अभियुक्त द्वारा अन्यत्र होने की दलील दी जाती है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा मौके पर उपस्थिति के संबंध में जिम्मेदारी स्थापित करने के बाद, सकारात्मक साक्ष्य द्वारा इसे स्थापित करने का दायित्व उस पर होता है। इस संदर्भ में, हम **बिनय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य (1997) 1 एससीसी 283** से कुछ पैराग्राफ को लाभप्रद रूप से पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं:

"22. हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि अन्यत्रता भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून में परिकल्पित कोई अपवाद (विशेष या सामान्य) नहीं है। यह केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 में मान्यता प्राप्त साक्ष्य का एक नियम है कि जो तथ्य संबंधित तथ्य से असंगत हैं वे प्रासंगिक हैं। प्रावधान के तहत दिया गया स्पष्टीकरण (ए) इस संदर्भ में पुनः प्रस्तुत करने लायक है:

"सवाल यह है कि क्या ए ने किसी निश्चित तारीख को कलकत्ता में अपराध किया था; यह तथ्य प्रासंगिक है कि उस तारीख को ए लाहौर में था।"

23. लैटिन शब्द अलीबी का अर्थ है "कहीं और" और उस शब्द का उपयोग सुविधा के लिए किया जाता है जब कोई आरोपी बचाव पक्ष का सहारा लेता है कि जब घटना घटी तो वह घटनास्थल से इतनी दूर था कि यह बेहद असंभव है कि उसने अपराध में भाग लिया होगा। यह एक बुनियादी कानून है कि एक आपराधिक मामले में, जिसमें आरोपी पर किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने का आरोप है, अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने की जिम्मेदारी है कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद था और उसने अपराध में भाग लिया था। केवल इस तथ्य से बोझ कम नहीं होगा कि अभियुक्त ने अन्यत्रता का बहाना अपना लिया है। ऐसे मामलों में अभियुक्त की याचिका पर तभी विचार किया जाना चाहिए जब अभियोजन पक्ष द्वारा बोझ का संतोषजनक ढंग से निर्वहन किया गया हो। लेकिन एक बार जब अभियोजन बोझ का निर्वहन करने में सफल हो जाता है तो यह अभियुक्त पर निर्भर होता है, जो अन्यत्र होने की दलील अपनाता है, इसे पूर्ण निश्चितता के साथ साबित करे ताकि घटना के स्थान पर उसकी उपस्थिति की संभावना को खत्म किया जा सके। जब अभियोजन पक्ष द्वारा विश्वसनीय साक्ष्यों के माध्यम से घटना स्थल पर अभियुक्त की उपस्थिति को संतोषजनक ढंग से स्थापित किया गया है, तो आम तौर पर न्यायालय इस आशय के किसी भी प्रति-साक्ष्य पर विश्वास करने में धीमी होगी कि घटना घटित होने के समय वह कहीं और था। लेकिन यदि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इतनी गुणवत्तापूर्ण और ऐसे मानक का है कि न्यायालय घटना के समय घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति के बारे में कुछ उचित संदेह मान सकती है, तो अभियुक्त निस्संदेह उस उचित संदेह के लाभ का हकदार होगा। उस उद्देश्य के लिए, यह एक उचित प्रस्ताव होगा कि, ऐसी

परिस्थितियों में, अभियुक्त पर बोझ काफी भारी होता है। इसलिए, इससे पता चलता है कि अन्यत्र होने की दलील को स्थापित करने के लिए सख्त सबूत की आवश्यकता होती है।[जोर दिया गया]

उक्त सिद्धांत को **गुरप्रीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2002) 8 एससीसी 18, एस.के. सत्तार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2010) 8 एससीसी 430 और जितेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2012) 6 एससीसी 204** मामले में दोहराया गया है।

24. उपरोक्त परीक्षण को लागू करते हुए, हमें रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य का एक्स-रे करना होगा। मृतक के पिता पीडब्लू-8 ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अपीलकर्ता-अभियुक्त घर पर था। प्रतिपरीक्षण में कुछ भी पता नहीं चला है। अभियोजन यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि घटना रात 11 बजे हुई थी। इस बात के निर्णायक चिकित्सीय साक्ष्य हैं कि मृतक को दुर्घटनावश लगी आग के कारण चोटें नहीं आईं। मृतक के पिता की गवाही पर अविश्वास करने या चिकित्सीय साक्ष्य को खारिज करने का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत, सबूत निंदा से परे है।

25. हमारी सुविचारित राय में, जब ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी अन्यत्रता की दलील पर अविश्वास किया है, जो तथ्य की समवर्ती खोज है, तो इसे खारिज करने का कोई आधार नहीं है। आरोपी द्वारा अन्यत्रता की दलील को साबित करने के लिए जो सबूत पेश किए गए हैं, वे अस्पष्ट हैं और वास्तव में तर्कसंगत नहीं हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अभियुक्त को पूर्ण निश्चितता के साथ साबित कर दिया गया है ताकि घटना के स्थान पर उसकी उपस्थिति की संभावना को बाहर किया जा सके। अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य ऐसी गुणवत्ता का नहीं है कि न्यायालय उचित संदेह पर विचार करे। आरोपी पर बोझ काफी भारी है और उसे अन्यत्रता की दलील को प्रमाणिकता के साथ स्थापित करना होता है। मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर

नहीं लाया गया है कि आरोपी की किसी अन्य स्थान पर उपस्थिति के कारण अपराध स्थल पर उसकी उपस्थिति की भौतिक असंभवता थी। याचिका तभी सफल हो सकती है जब यह दिखाया जाए कि आरोपी प्रासंगिक समय पर इतना दूर था कि वह उस स्थान पर मौजूद नहीं हो सकता था जहां अपराध किया गया था। **[देखें दूध नाथ पांडे बनाम यूपी राज्य (1981) 1 एससीसी 166]**। बहन, DW-1 का साक्ष्य किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। घटना स्थल पर आरोपी की मौजूदगी के संबंध में साक्ष्य के संचयी प्रभाव पर बहन के मामूली बयान के आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है, जो न केवल अधूरा है बल्कि तर्क को भी झुठलाता है। इसलिए, हम विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा इस वजह पर दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत होने के लिए बाध्य हैं, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन की मुहर लगाई गई है।

26. नतीजतन, अपील, योग्यता से रहित होने के कारण, खारिज कर दी जाती है।

अपील खारिज.

कल्पना के. त्रिपाठी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता अनिल जोशी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।